

दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट के खिलाफ FIR दर्ज, यात्रि पर हमला करने की शिकायत दर्ज



नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिस पर आरोप है कि उसने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टर्मिनल-1) पर एक यात्रि को मारपीट करके घायल कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब घायल यात्रि अंकित दीवान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि पायलट ने उसे शारीरिक रूप से घायल किया और उसकी लहलहात तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिससे पुलिस को घटना की जानकारी मिली और FIR दर्ज की गई।

अन्य रिपोर्टों के अनुसार शिकायत में यह भी बताया गया है कि विवाद सिक्कोरिटी जांच की कतार में मामूली तकरार के बाद शुरू हुआ था और पायलट ने उससे पहले अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और फिर शारीरिक हमला किया। घायल यात्री ने कहा कि उसकी 7-साल की बेटी ने भी यह सब देखा, जिससे परिवार को मानसिक आघात भी पहुंचा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपी पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है तथा जांच जारी है। पुलिस ने आरोपों की जांच के लिए संबंधित CCTV फुटेज और सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

WORLD NEWS | अमेरिका ने भारत के नए शांति बिल का स्वागत किया है

खुश हुआ अमेरिका, भारत के इस कदम का किया स्वागत; नए SHANTI कानून को बताया बड़ा कदम

नई दिल्ली | अमेरिका ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए ' भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक' का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा कि वो भारत के SHANTI बिल का स्वागत करता है, जो एक मजबूत एनर्जी सिक्कोरिटी पार्टनरशिप और शांतिपूर्ण सिविल न्यूक्लियर सहयोग की दिशा में एक कदम है। भारत के नए शांति बिल का स्वागत नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने X पोस्ट में कहा, 'हम भारत के नए #SHANTIBill का स्वागत करते हैं, जो एक मजबूत एनर्जी सिक्कोरिटी पार्टनरशिप और शांतिपूर्ण सिविल न्यूक्लियर सहयोग की दिशा में एक कदम है। अमेरिका एनर्जी सेक्टर में जॉइंट इनोवेशन, अनुसंधान और विकास करने के लिए तैयार है।'

राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बना शांति बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 दिसंबर को संसद के



शीतकालीन सत्र में पारित 'भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक' को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक नागरिक परमाणु क्षेत्र से संबंधित सभी कानूनों को समाहित करता है और साथ ही इसे निजी

क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोलता है। शांति विधेयक ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त कर दिया। यह निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को सरकार से लाइसेंस प्राप्त

करके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व, संचालन करने में सक्षम बनाता है। मोदी ने शांति बिल पारित होने पर जताई थी खुशी बीते गुरुवार को राज्यसभा से 'द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025', यानी शांति विधेयक, 2025 से भी पारित हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई थी। पीएम मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति विधेयक का पारित होना हमारे प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी क्षण है। इसके पारित होने में सहयोग देने वाले सांसदों के प्रति मेरी कृतज्ञता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सुरक्षित रूप से संचालित करने से लेकर हरित विनिर्माण को सक्षम बनाने तक, यह विधेयक देश और विश्व के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को निर्णायक गति प्रदान करता है। यह निजी क्षेत्र और हमारे युवाओं के लिए भी अनेक अवसर खोलता है। भारत में निवेश करने, नवाचार करने और विकास करने का यह सबसे उपयुक्त समय है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत का राहुल गांधी को फोन – विपक्षी एकता और बीएमसी चुनाव की रणनीति

नई दिल्ली | 22 दिसंबर 2025: महाराष्ट्र में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों ने राजनीति का समीकरण बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-शिंदे गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद विपक्षी खेमे में चिंता और रणनीति दोनों तेज़ी से उभर रही हैं। इसी बीच शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फोन कर चर्चा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए विपक्षी एकता पर विचार करना बताया जाता है।



जिससे विपक्षी दलों को मिलकर रणनीति बनानी जरूरी हो गई है। राउत ने राहुल गांधी को फोन कर भाजपा-शिंदे को रोकने हेतु एमवीए (महा विकास अघाड़ी) के घटकों के बीच समन्वय बढ़ाने की बात कही। यह बातचीत 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले विपक्ष की स्थिति मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। राउत ने बातचीत

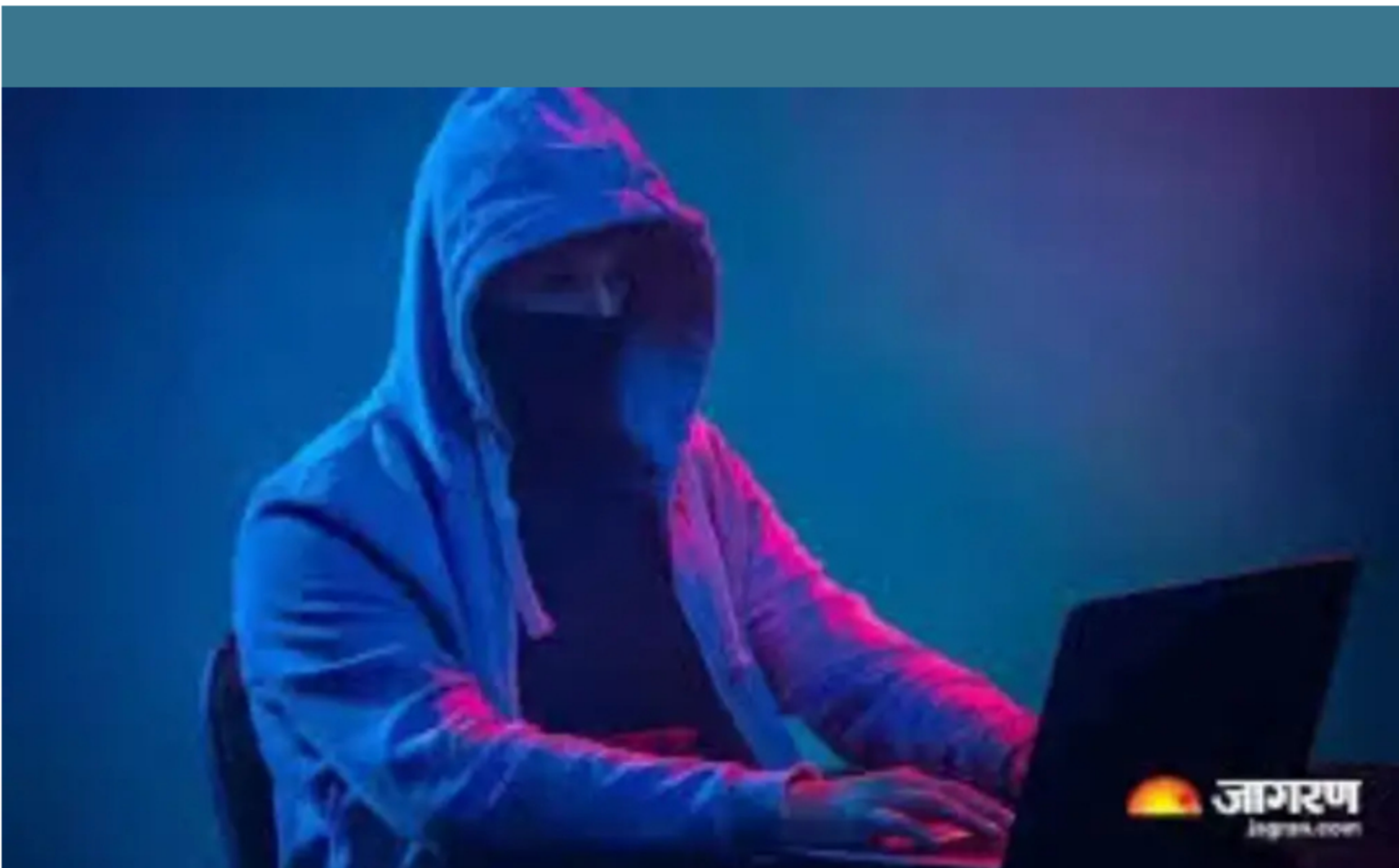
में भाजपा के खिलाफ एकजुटता और मिलकर लड़ने पर ज़ोर दिया, जबकि कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। शिवसेना (उबठा) नेतृत्व यह मानता है कि एक संयुक्त मोर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा-शिंदे गठबंधन को चुनौती दे सकता है।

हालाँकि, कांग्रेस ने मनसे (राज ठाकरे) के साथ गठबंधन पर असहमति जताई है और अपनी स्वतंत्र चुनाव लड़ने की स्थिति स्पष्ट रखी है। इस दुविधा के बीच राउत का प्रयास यह दर्शाता है कि विपक्षी दलों के बीच सामंजस्य की कमी बीएमसी चुनाव की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो मतों के बंटवारे से भाजपा-शिंदे गठबंधन को फायदा मिल सकता है। इसीलिए राउत का कॉल सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि आगामी बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

देहरादून में शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 1.30 करोड़ रुपये की साइबर ठगी, वाट्सएप ग्रुप में जोड़कर पैसे ऐंठे गए

देहरादून: साइबर ठगों ने पौड़ी जिले के एक सरकारी कर्मचारी सुरेश कुमार से लगभग 1.30 करोड़ रुपये की ठगी की है। आरोपी पहले उन्हें WhatsApp ग्रुप में शामिल करते थे और फिर शेयर मार्केट निवेश से भारी मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर पैसे जमा करवाते रहे। यह ठगी करीब डेढ़ माह तक चली।

सुरेश ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें 6 अक्टूबर को एक लिंक के माध्यम से ग्रुप में जोड़ा। ग्रुप एडमिन का दावा था कि "DBS ग्रुप" तीन नवंबर से डेली ट्रेडिंग प्लान चला रहा है, जिसमें रोज़ाना लगभग 5% मुनाफा मिलने का वादा किया गया। इसके बाद ठगों ने उन्हें इंटरनल इक्रीटी खाते में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा और 4 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कुल 1.30 करोड़ रुपये जमा करा लिए।



उनके निवेश खाते में लगभग 30 करोड़ रुपये का नकली बैलेंस दिखाया गया, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो उनसे और धनराशि जमा कराने को कहा गया। सुरेश ने बताया कि उन्होंने अपनी सारी जीवन की बचत और दोस्तों के कुछ पैसे भी निवेश कर दिए थे।

जब निकासी संभव नहीं हुई तो उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, देहरादून में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना अन्य निवेश योजनाओं और ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखों से सावधान रहने की चेतावनी भी देती है।

छत्रपती संभाजीनगर: रशीद मामू के शिवसेना (उद्धव ठाकरे) में प्रवेश से पार्टी में विवाद, खैरे-दानवे में टकराव



संवाददाता |

छत्रपती संभाजीनगर: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) में माजी महापौर रशीद खान उर्फ 'मामू' को शामिल किए जाने से पार्टी के भीतर भारी विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला नगरपालिका चुनाव की तैयारियों के बीच सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे ने कहा है कि रशीद मामू को पार्टी में प्रवेश देने का निर्णय भारी गलत था, क्योंकि मामू पर पहले दंगा और दाड़फेक जैसे आरोप लगे थे, जिससे पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। खैरे का यह भी दावा है कि इससे लगभग 50,000 हिंदू मतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पार्टी को नुकसान होगा।

अंबादास दानवे पर भी खैरे ने आरोप लगाए हैं, कहा कि उन्होंने बिना मंथन किए रशीद मामू का प्रवेश करवा दिया। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी को 'उबाठा मामू पार्टी' कहकर भी आलोचना की, जिससे विवाद और बढ़ गया है।

खैरे ने स्पष्ट किया कि मामू को उम्मीदवारी (ticket) नहीं दी जाएगी और पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। यह विवाद शिवसेना के अंदर रणनीति और छवि को लेकर मतभेद को उजागर करता है, खासकर जब स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हैं।



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/गुवाहाटी: असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी (BJP) बांग्लादेश और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।

असम चुनाव में बांग्लादेश और घुसपैठियों पर BJP का फोकस; 26-27 दिसंबर को रणनीति बैठक तय

यही वजह है कि पार्टी 26 और 27 दिसंबर 2025 को असम चुनाव से जुड़ी रणनीति तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगी जिसमें राष्ट्रीय और राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की सक्रिय भागीदारी होगी और आगामी चुनाव घोषणापत्र तथा प्रचार अभियान की दिशा तय की जाएगी।

असम बीजेपी की तय रणनीति का केंद्र "घुसपैठ" का मुद्दा है जिसे पार्टी के नेता स्थानीय असम की पहचान, सुरक्षा और विकास से जोड़कर प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम

दौरे और गृहमंत्री अमित शाह के संभावित आगामी दौरे के जरिए भी इस मुद्दे को जनता के सामने उठाने का संकेत दिया है। पार्टी का कहना है कि यह मुद्दा सीमावर्ती जिलों के निवासियों के लिए बेहद संवेदनशील है और मतदान के दौरान व्यापक जनसमर्थन जुटा सकता है।

असम बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वह विकास कार्यों और केंद्र तथा राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी उभारते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को चुनावी फोकस में रखेगी। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया पर भी असम में "बांग्लादेशी घुसपैठियों" के बारे में सतर्कता बनाए रखने की

बात कही है और कहा है कि यह मुद्दा जनता की भावनाओं तथा सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विषय न सिर्फ मतदाताओं में संभावनात्मक रूप से गहराई रखता है, बल्कि पहचान, रोजगार और संसाधनों की उपलब्धता जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है, जो असम में चुनावी बहस को और तीव्र बना सकता है। इस घोषणा से असम के आगामी चुनाव संवाद और राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर भी असर पड़ने की संभावनाएँ बन रही हैं।





संपादकीय अग्रलेख | स्थानीय चुनावों के बाद महाराष्ट्र में लोकतंत्र और साम्प्रदायिक सौहार्द की जिम्मेदारी

संपादकीय... |

महाराष्ट्र में 21 दिसंबर 2025 को हुए नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद आज, 22 दिसंबर को, पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र यही चुनाव बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी, एआईएमआईएम (मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन), अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों को जनता ने विभिन्न क्षेत्रों में जनादेश दिया है। यह परिणाम महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक विविधता और मतदाताओं की स्वतंत्र सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

स्थानीय निकाय चुनाव किसी एक दल या विचारधारा की निर्णायक जीत से अधिक, जनता की स्थानीय अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होते हैं। नगरपालिकाएं और नगर पंचायतें नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी संस्थाएं हैं, जहां पानी, सफाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे प्रमुख होते हैं। यही कारण है कि मतदाताओं ने कई स्थानों पर राष्ट्रीय दलों को समर्थन दिया, तो कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों, स्थानीय पैनलों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। यह प्रवृत्ति इस बात का संकेत है कि महाराष्ट्र का मतदाता केवल पहचान या भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यक्षमता और भरोसे के आधार पर निर्णय ले रहा है।

इन चुनावों में भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के साथ-साथ एआईएमआईएम की उपस्थिति और कुछ स्थानों पर उसका प्रदर्शन भी चर्चा में रहा है। साथ ही, निर्दलीय उम्मीदवारों की सफलता यह दिखाती है कि स्थानीय नेतृत्व और व्यक्तिगत विश्वसनीयता आज भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह स्थिति किसी एक पार्टी की सर्वव्यापकता नहीं, बल्कि बहुदलीय व्यवस्था की जीवंतता को दर्शाती है।

हालांकि, चुनाव परिणामों के बाद सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक जीत या हार नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के दौरान विचारों का टकराव स्वाभाविक है, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद सभी दलों और समर्थकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे संयम और परिपक्वता का परिचय दें। किसी भी दल की जीत को किसी विशेष समुदाय की जीत और हार को किसी समुदाय की हार के रूप में प्रस्तुत करना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी घातक है।

महाराष्ट्र की परंपरा समावेशी रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन से लेकर संत परंपरा और समाज सुधार आंदोलनों तक, इस राज्य ने हमेशा सामाजिक समरसता और सहअस्तित्व को महत्व दिया है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी यही मूल्य मार्गदर्शक होने चाहिए। भाजपा हो या कांग्रेस, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी, एआईएमआईएम हो या निर्दलीय प्रतिनिधि—सभी को यह समझना होगा कि वे केवल अपने मतदाताओं के नहीं, बल्कि पूरे नगर और पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं।

प्रशासन और स्थानीय शासन तंत्र की भूमिका भी इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अफवाहों पर नियंत्रण रखना और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना—यही प्रशासन की विश्वसनीयता की कसौटी है। साथ ही, मीडिया और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे अप्रुष्ट या भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन नफरत फैलाने का नहीं।

अंततः, इन स्थानीय चुनावों का असली संदेश यही है कि महाराष्ट्र का लोकतंत्र बहुआयामी और जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी, अलग-अलग दलों, एआईएमआईएम, और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला जनसमर्थन यह दर्शाता है कि जनता विकल्प चाहती है और जवाबदेही की अपेक्षा रखती है। अब यह सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर विकास, पारदर्शिता और सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करें। यदि राजनीति समाज को जोड़ने का माध्यम बने, तो यही इन चुनावों की सबसे बड़ी और सच्ची सफलता होगी।

बांग्लादेश ने तीन भारतीय शहरों में बंद की वीजा सर्विस, जानें क्या कारण बताया

ढाका | बांग्लादेश ने अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए नई दिल्ली, अगरतला और सिलीगुड़ी में अगली सूचना तक सभी कांसुलर सेवाओं और वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। बांग्लादेशी मीडिया द डेली स्टार ने बताया कि दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के अपने बोर्ड पर लगाए गए एक नोटिस में कहा गया है, "अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण, नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अगली सूचना तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।"

बांग्लादेश ने क्यों बंद की वीजा सर्विस

यह कदम तब उठाया गया जब अखंड हिंदू राष्ट्र सेना के कुछ सदस्यों ने शनिवार को दिल्ली में हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में लिंगिंग के बाद जलाए गए 27 वर्षीय हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद विरोध में किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने की मांग की। उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल



बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इसी दौरान चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर बृहस्पतिवार को पथराव की घटना भी हुई। नकाबपोश बंदूकधारियों ने 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर क्षेत्र में इंकलाब मंच के प्रवक्ता हादी के सिर में उस समय गोली मार दी थी, जब वह चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के प्रमुख नेता रहे हादी 12 फरवरी को होने वाले आम

चुनावों के लिए उम्मीदवार थे। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी।

भारत ने भी चटगांव में वीजा सेवा निलंबित की। भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (आईवीएसी) ने एक बयान में कहा कि चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग में हाल में हुई घटना के कारण आईवीएसी में सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। आईवीएसी के अनुसार, बंदरगाह शहर में भारतीय वीजा संबंधी सभी सेवाएं 21 दिसंबर से अगले आदेश तक बंद रहेंगी।

बयान में कहा गया कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद वीजा आवेदन केंद्र को फिर से खोलने के संबंध में आगे की घोषणा की जाएगी।

बांग्लादेश में भारतीय मिशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई

बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। आईवीएसी ढाका, खुलना और राजशाही, चटगांव और सिलहट में केंद्र संचालित करता है। आईवीएसी के एक अधिकारी ने बताया कि चार अन्य कार्यालय चालू हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को ढाका में अपने वीजा आवेदन केंद्र को फिर से खोल दिया। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण एक दिन पहले इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन राजशाही और खुलना में दो अन्य केंद्रों को संक्षिप्त अवधि के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों ने वहां भारतीय दूतावासों की ओर मार्च करने का प्रयास किया था। शनिवार को बांग्लादेश के सिलहट शहर में भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

Top News

भारत के इन हथियारों से कांप रहा था पाकिस्तान

अल्लाह ने मदद की: मुनीर ने माना, भारत के इन हथियारों से कांप रहा था पाकिस्तान

नई दिल्ली: कहते हैं कि सच्चाई एक न एक दिन खुद ही सामने आ जाती है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तानी फौज के चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ। उन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को 'अल्लाह से मदद' मिली। पाकिस्तानी सेना चीफ इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उनके दिल में छिपी सच्चाई उनकी जुबां पे आ गई। चार दिन के इस सैन्य संघर्ष में भारतीय सशस्त्र सेना ने पहले पाकिस्तान और उसके कब्जे वाली कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकाने तबाह किए थे और फिर पाकिस्तान के उकसावे के बाद उसके सैन्य ठिकाने और एयरफोर्स बेस को मिट्टी में मिला दिया था।

'हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी' पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जेनरल फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कबूल किया है कि भारत के साथ मई में सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान और उसकी सेना को अल्लाह से

सहायता मिली, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उन्होंने कहा, '...और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की...हमने महसूस किया।' दरअसल, भारी तबाही के बाद थर-थर कांप रही पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से फौरन सीजफायर की अपील की थी, तब जाकर भारत ने पाकिस्तानी सेना पर अपनी जवाबी कार्रवाई रोक दी थी।

पाकिस्तान के अनुरोध पर रुका ऑपरेशन बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस हमले कुल 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक की पाकिस्तानी आतंकियों ने बेरहमी से कल्ल कर दिया था। इसके जवाब में भारत की ओर से शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कुल चार दिन चला और 10 मई को पाकिस्तानी सेना के अनुरोध पर ऑपेशन सिंदूर पर अस्थायी ब्रेक लगा दिया गया।



भारत के इन हथियारों से कांपा था पाकिस्तान

शुरू में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों और बाद में पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत ने कुल 4 महत्वपूर्ण घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्ड क्रूज मिसाइल स्कैल्प (SCALP), प्रिसिजन-गाइडेड बॉम्ब हैमर (HAMMER-Highly Agile Modular Munition Extended Range) और कामिकेज या लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन शामिल हैं।

दुश्मन पर किए थे अचूक और घातक हमले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां भारत की ओर से राफेल फाइटर जेट से स्कैल्प और हैमर म्यूनिशन दागे गए, वहीं सुखोई एसयू-30एमकेआई से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गईं। वहीं, स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और रूसी एस-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी आक्रमण को नाकाम करने में बड़ी सहायता की।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Tuesday 23rd December 2025 वर्ष - 9 , अंक 237 , पृष्ठ 03

एसबीआई अहिल्यानगर मुख्य शाखा में 3.77 करोड़ रुपये के गबन का आरोप, अधिकारी और पत्नी समेत अन्य व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज



संवाददाता |

अहिल्यानगर (महाराष्ट्र): स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की मुख्य शाखा में लगभग ₹3.77 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने बैंक के सीनियर असोसिएट अधिकारी, उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्याद (FIR) दर्ज की है। आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई फिक्स्ड डिपॉजिट खातों को बिना अनुमति बंद किया और राशि को स्वयं और नाते-रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किया।

घटना तब उजागर हुई जब शाखा प्रमुख ने

मई 2025 में असामान्य वित्तीय गतिविधियों का पता लगाया। जांच में पता चला कि अधिकारी ने 22 और 53 फिक्स्ड डिपॉजिट खातों को अवैध रूप से बंद कर ₹3.77 करोड़ से अधिक की राशि अपने लाभ के लिए इस्तेमाल की।

पुलिस ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने नकली चेक, दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड में फेरबदल कर धोखाधड़ी की। मामले की जांच भिंगार कैप पुलिस कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

NANDED NEWS | नांदेड में ठाकरे गुट के प्रत्याशी की बड़ी जीत

प्रचार में दिग्गजों ने बनाई दूरी, जनता बनी ताकत; नांदेड में ठाकरे गुट के प्रत्याशी की बड़ी जीत

नांदेड | नांदेड जिले में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के हाल ही में संपन्न चुनावों के नतीजे आज घोषित किए गए, जिनमें कई स्थानों पर चौकाने वाले परिणाम सामने आए। जिले के किनवट नगर परिषद चुनाव में शिवसेना (ठाकरे गुट) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया है। ठाकरे गुट की उम्मीदवार सुजाता एंड्रलवार ने भाजपा प्रत्याशी को करीब चार हजार मतों के बड़े अंतर से हराकर नगराध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया।

किनवट नगर परिषद में सुजाता एंड्रलवार ने भाजपा की पुष्पा माचेवार को 3,996 मतों से पराजित किया। सुजाता एंड्रलवार को कुल 10,473 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 8,477 मतों पर संतोष करना पड़ा। खास बात यह रही कि चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना (ठाकरे गुट) के शीर्ष नेताओं—पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे



और सुष्मा अंधारे—की कोई भी सभा नहीं हुई। इसके बावजूद स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा जनता के समर्थन से ठाकरे गुट को यह अहम सफलता मिली। किनवट क्षेत्र भाजपा विधायक भीमराव केराम का निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और इसे भाजपा का गढ़ समझा जाता रहा है। ऐसे में वरिष्ठ

नेताओं की गैरमौजूदगी के बावजूद ठाकरे गुट की जीत को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव में ठाकरे गुट ने नगराध्यक्ष पद के साथ-साथ तीन नगरसेवक सीटें भी जीती हैं।

नांदेड जिले के किनवट, हदगांव, धर्माबाद और लोहा नगर परिषदों तथा

हिमायतनगर नगर पंचायत में विभिन्न दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लोहा नगर परिषद में ठाकरे गुट के एक नगरसेवक, हिमायतनगर में तीन और हदगांव में सात नगरसेवक निर्वाचित हुए हैं। जिलेभर के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो भाजपा को 3 नगराध्यक्ष और 74 नगरसेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) को 3 नगराध्यक्ष और 70 नगरसेवक, कांग्रेस को 2 नगराध्यक्ष और 42 नगरसेवक, शिवसेना (शिंदे गुट) को 2 नगराध्यक्ष और 15 नगरसेवक मिले हैं। वहीं मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने 2 नगराध्यक्ष और 33 नगरसेवक जीते हैं। शिवसेना (ठाकरे गुट) को 1 नगराध्यक्ष और 14 नगरसेवक, राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) को 5, एमआईएम को 2, वंचित बहुजन आघाड़ी को 1 तथा 12 नगरसेवक निर्दलीय चुने गए हैं।

इन नतीजों ने नांदेड जिले की स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दे दिए हैं।

मराठवाड़ा निकाय चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी – 52 नगराध्यक्षों में से 39 महायुति के झंडे तले



छत्रपती संभाजीनगर (नांदेड/मराठवाड़ा): मराठवाड़ा क्षेत्र में नगरपरिषदों और नगर पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आज घोषित किए गए, जिसमें महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी-अजित पवार) ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, जिससे 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम दोहराया गया है।

आठ जिलों में कुल 52 नगराध्यक्ष पदों में से महायुति गठबंधन ने 39 पदों पर विजय पाई। इसमें से सबसे अधिक 17 नगराध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीते,

जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है।

शिवसेना-शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) ने भी दमदार प्रदर्शन किया और प्रत्येक ने 11-11 नगराध्यक्ष पद हासिल किए। इसके विपरीत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) तथा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को केवल 2-2 नगराध्यक्ष पदों से संतोष करना पड़ा, जिससे उनकी चुनावी पकड़ कमजोर दिखाई दी।

भाजपा ने विशेष रूप से लातूर जिले में दमदार प्रदर्शन किया, जहां 5 में से 4 नगराध्यक्ष पद उसने

जीते। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जैसे छत्रपती संभाजीनगर तथा बीड, भाजपा को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। हिंगोली के नगर परिषदों में शिवसेना-शिंदे गुट का दबदबा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, महायुति की यह जीत स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ता-समर्थन की जनता-मान्यता का प्रतिबिंब है और यह आगामी 2026 के निकाय चुनावों के लिए भी दिशा-निर्धारक मानी जा रही है।

कांग्रेस ने कुछ जिलों में अपेक्षित प्रदर्शन करते हुए छत्रपती संभाजीनगर और नांदेड में दो-दो तरह

नगराध्यक्ष पद जीते, लेकिन वह महायुति की तुलना में अधिक प्रभाव नहीं बना सकी।

कुल मिलाकर, महायुति गठबंधन ने स्थानीय निकायों में स्पष्ट बहुमत दर्ज किया, जिसमें भाजपा प्रमुख भूमिका में रही है, जबकि उद्धव-गुट शिवसेना और शरद पवार समूह की उपस्थिति सीमित रही। यह विजय मराठवाड़ा में सत्ता समीकरण को पुनः स्थापित करती है और आगामी नगर निगम चुनावों के लिए पूरे राज्य में राजनीतिक संदेश देती है कि महायुति स्थानीय स्तर पर भी मजबूत समर्थन के साथ लौट आई है।

रोहित पवार का कांग्रेस पर “बी-टीम” का आरोप, बाळासाहेब थोरात ने किया पलटवार

जामखेड/महाराष्ट्र। स्थानीय निकाय चुनावों में पराजय के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस भाजपा की “बी-टीम” के रूप में काम कर रही है। रोहित पवार ने पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जामखेड नगरपालिका चुनाव में भाजपा के पक्ष में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को टिकट दिया, जिससे भाजपा को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के बावजूद यह कदम निराशाजनक है और इससे कांग्रेस की साख पर सवाल उठते हैं।

रोहित पवार ने यह भी टिप्पणी की कि स्थानीय चुनाव में जीत के लिए पैसों के प्रभाव और लोकल राजनीति में साफ-सुथरे तरीके की कमी ने पारंपरिक



राजनैतिक मूल्यों को कमजोर किया है। उनकी प्रतिक्रिया से महाविकास आघाड़ी में मतभेद और बढ़ता विवाद साफ नजर आ रहा है। उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाळासाहेब थोरात ने रोहित पवार के आरोपों का पलटवार किया है। थोरात ने कहा कि रोहित पवार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं करते और इस

कारण से असंतोष पैदा हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर संगठनात्मक समन्वय और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल से ही पार्टी का भविष्य मजबूत होगा। इस विवाद से महाविकास आघाड़ी के भीतर तनाव बढ़ा है और आने वाले समय में गठबंधन के भीतर समन्वय के मुद्दे राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।

शनि शिंगणापुर की तरह: बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का विवादित बयान, “हमारी पार्टी के भी दरवाजे खुले हैं” वीडियो वायरल

संवाददाता |

नागपुर: भाजपा के वरिष्ठ नेता और मझगांव विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने एक बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक माहौल गरम है, और इसी बीच मुनगंटीवार ने कहा कि “जैसे शनि शिंगणापुर में घरों के दरवाजे नहीं होते, वैसे ही हमारी पार्टी के भी दरवाजे खुले हैं, कोई भी आता है, कोई भी जाता है।” यह बयान पार्टी में लोगों के शामिल होने और छोड़ने की स्थिति पर चिंता व्यक्त करने जैसा माना जा रहा है।

उनके इस बयान से भाजपा के आंतरिक एकता और संगठनात्मक मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। मुनगंटीवार के बयान से यह संकेत मिलता है कि पार्टी में कुछ गुटबाजी और असंतोष व्याप्त है, खासकर उन नेताओं के शामिल होने के बाद जिन्हें हाल ही में पार्टी में शामिल किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बयान सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह भाजपा की स्थिरता और निर्णय प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में लिया जा रहा है।



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

२०२९ में महायुति साथ ही लड़ेगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी २०२९ के विधानसभा चुनावों में महायुति (बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपनी पुष्टि की है, जिससे सियासी चर्चाओं में बड़ा मोड़ आया है।

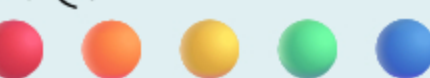
सत्ता में महायुति की वर्तमान मजबूती के बीच यह सवाल उठ रहा था कि क्या २०२९ में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ ही मैदान में उतरेगी। केंद्रीय नेतृत्व के कुछ समीकरणों के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा को अपने सहयोगियों की आवश्यकता है, इसलिए महायुति स्पष्ट रूप से साथ

ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सहयोगियों के साथ मतभेद होना सामान्य है, लेकिन उससे गठबंधन कमजोर नहीं होता। फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद हैं, लेकिन दोनों के बीच “किसी प्रकार का विवाद नहीं है” और दोनों एक परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे हमेशा एक ही राय रखते तो अलग दलों में नहीं होते, लेकिन व्यापक तौर पर वे साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भरोसा जताया कि महायुति के सहयोग से बीजेपी राज्य में और मजबूती से उभर

सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब पार्टी मजबूत हो जाए तो सहयोगियों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि २०२९ के विधानसभा चुनाव महायुति के साथ ही लड़े जाएंगे, न कि भाजपा अकेले चुनाव का सामना करेगी।

राजनीतिक टिप्पणीकारों का मानना है कि फडणवीस का यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता बनाए रखने की इच्छा और गठबंधन बल को बरकरार रखने की रणनीति का संकेत है, खासकर ऐसे समय जब स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति ने भारी सफलता हासिल की है।







AIMIM की महाराष्ट्र निकाय चुनावों में शानदार सफलता: 83 पार्षद जीते, कारंजा में अध्यक्ष पद पर कब्जा

मुंबई/अकोला, 22 दिसंबर 2025: असदुद्दीन औवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पार्टी ने कुल 83 पार्षद सीटों जीतीं और वाशिम जिले की कारंजा लाड नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर भी विजय हासिल की। यह जीत पार्टी के लिए राज्य में स्थानीय स्तर पर मजबूत आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चुनाव परिणामों के अनुसार, AIMIM की उम्मीदवार फरीदा बानो मोहम्मद शफी पुंजानी ने कारंजा में भाजपा की निशा गोलछा को मात्र 110-117 मतों के अंतर से हराकर अध्यक्ष पद जीता। पार्टी ने यहां कई पार्षद सीटें भी अपने नाम कीं। अन्य प्रमुख जगहों पर AIMIM ने अकोला, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, नंदुरबार और जलगांव जैसी नगर परिषदों में अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह जीत विकास, न्याय और मजबूत नेतृत्व पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। AIMIM

Election News | कांग्रेस को 5, उद्धव सेना को 7 और महागठबंधन को 8 नगरसेवक सीटें

पूर्व सांसद की बहू को जनता का जनादेश, रोहिणी वानखेड़े बनीं हदगांव नगराध्यक्ष



शिवसेना की प्रत्याशी रोहिणी वानखेड़े ने कांग्रेस की उम्मीदवार कोमुद सुनील सोनुले को 1,293 मतों के अंतर से पराजित किया। इस चुनाव में महागठबंधन के कुल 8 नगरसेवक निर्वाचित हुए हैं।

नगर परिषद के 10 प्रभागों के लिए कुल 73 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि नगराध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। मतगणना के पहले ही दौर में भाजपा के दो और कांग्रेस के दो उम्मीदवारों के निर्वाचित होने से मुकाबला रोचक बन गया। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से शिवसेना का गढ़ माना जाता है, इसके बावजूद शुरुआती दौर में कांग्रेस प्रत्याशी कोमुद सोनुले ने पांच मतों की बढ़त बना ली थी। हालांकि बाद की गिनती में रोहिणी वानखेड़े ने बढ़त हासिल कर अंत तक बनाए रखी।

तीन दौर की मतगणना तक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का खाता नहीं

खुला था, लेकिन इसके बाद प्रभाग 5-अ, 7-अ, 7-ब, 8-अ, 8-ब, 9-अ और 9-ब में उद्धव सेना ने जीत दर्ज करते हुए कई दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी। वहीं प्रभाग 2 और 3 में कांग्रेस को सफलता मिली। पूर्व नगराध्यक्ष अमित अडसूळ भी विजयी रहे, हालांकि उनके प्रभाग में नगराध्यक्ष पद के लिए शिवसेना को नेतृत्व प्राप्त हुआ।

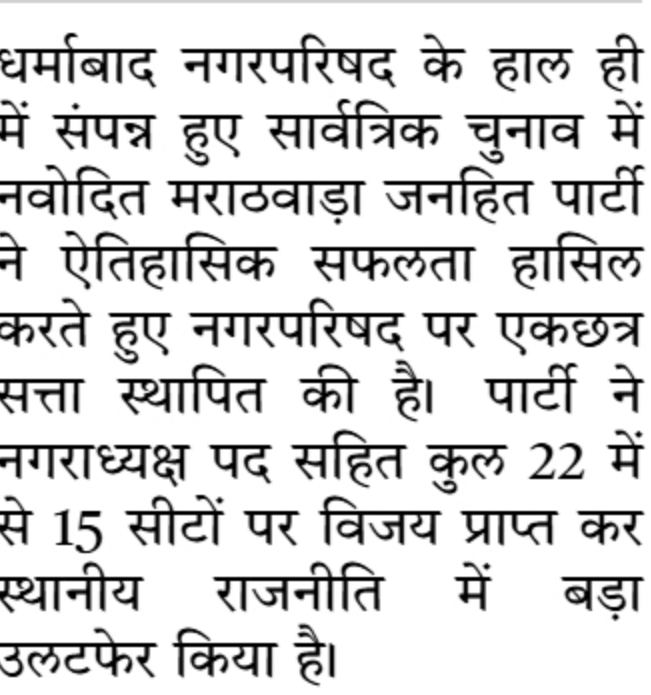
प्रभाग 4 में शिवसेना और भाजपा के अलग-अलग उम्मीदवार मैदान में होने से मतों के बंटवारे की आशंका थी, जिससे कांग्रेस को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही थी। बावजूद इसके, शिवसेना और भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे। कई प्रभागों में चौकाने वाले नतीजे सामने आए, जहां मतदाताओं ने पार्टी से अधिक उम्मीदवार की छवि और कार्यक्षमता को प्राथमिकता दी।

उद्धव सेना का प्रभावशाली प्रदर्शन पिछले चुनाव में जब शिवसेना एकजुट

थी और विधायक भी शिवसेना से थे, तब भी पार्टी को केवल आठ सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस बार उद्धव सेना के सांसद नागेश आष्टीकर ने गठबंधन के लिए सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक की ओर से सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने स्वतंत्र पैनल उतारा। नतीजतन, 20 में से 7 सीटों पर उद्धव सेना ने अपना दबदबा कायम किया।

कांग्रेस को पांच सीटों पर संतोष पिछले दस वर्षों से सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस के प्रति मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा। महिला आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने रणनीतिक दांव खेलते हुए सुनील सोनुले को आगे किया और अनुसूचित जाति व मुस्लिम मतों को साधने की कोशिश की। हालांकि यह रणनीति सफल नहीं हो सकी और रोहिणी वानखेड़े ने कांग्रेस की इस चाल को विफल कर दिया।

धर्माबाद नगरपरिषद पर मराठवाड़ा जनहित पार्टी का ऐतिहासिक वर्चस्व



धर्माबाद नगरपरिषद के हाल ही में संपन्न हुए सार्वत्रिक चुनाव में नवोदित मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए नगरपरिषद पर एकछत्र सत्ता स्थापित की है। पार्टी ने नगराध्यक्ष पद सहित कुल 22 में से 15 सीटों पर विजय प्राप्त कर स्थानीय राजनीति में बड़ा उलटफेर किया है।

नगराध्यक्ष पद के लिए हुए सीधे चुनाव में मराठवाड़ा जनहित पार्टी की उम्मीदवार संगीता महेश बोलमवार विजयी रही। उनके साथ पार्टी के 15 नगरसेवक भी चुने गए, जिससे नगरपरिषद में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इस परिणाम को क्षेत्र में बदलाव की मजबूत शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा और वह केवल 7 सीटों तक

सिमट गई। कांग्रेस, दोनों शिवसेनाएं, दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस दल, समाजवादी पार्टी और एमआईएम जैसे प्रमुख दल एक भी सीट जीतने में असफल रहे। चुनाव में नगराध्यक्ष पद के लिए 9 और नगरसेवक पदों के लिए 125 उम्मीदवार मैदान में थे। कड़े मुकाबले के बावजूद मतदाताओं ने

मराठवाड़ा जनहित पार्टी को स्पष्ट समर्थन दिया। पार्टी के संस्थापक-अध्यक्ष महेश बोलमवार और मोईजशेठ बीडीवाले की मजबूत संगठनात्मक रणनीति और जनसंपर्क को इस जीत का मुख्य कारण माना जा रहा है। यह जनादेश धर्माबाद की राजनीति में नई शक्ति के उदय का संकेत देता है।

राष्ट्रवादी के समर्थन से उद्धवसेना की जीत, भाजपा विधायक को करारा झटका, किनवट नगराध्यक्ष चुनाव में सुजाता एंड्रलवार का एकतरफा विजय



किनवट | नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद हुए नगराध्यक्ष पद के चुनाव में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की उम्मीदवार सुजाता विनोद एंड्रलवार ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पुष्पा आनंद मच्छेवार को बड़े अंतर से पराजित किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के समर्थन से यह मुकाबला एकतरफा साबित हुआ, जिससे भाजपा विधायक भीमराव केराम को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।

शुरुआत में बेहद कांटे की टक्कर मानी जा रही यह चुनावी लड़ाई नतीजों में पूरी तरह पलट गई। भाजपा विधायक भीमराव केराम ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था, वहीं दूसरी ओर शिवसेना (उबाठा) के जिला प्रमुख ज्योतिबा खराटे तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की ओर से दिवंगत पूर्व विधायक प्रदीप नाईक की पत्नी

बेबीताई नाईक और पुत्र कपिल नाईक ने चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई। मतदाताओं ने भाजपा विधायक को नकारते हुए नगर परिषद की सत्ता शिवसेना (उबाठा) के हाथों में सौंप दी। नगराध्यक्ष पद के चुनाव में सुजाता विनोद एंड्रलवार को 10,473 मत, जबकि भाजपा की पुष्पा आनंद मच्छेवार को 6,477 मत प्राप्त हुए।

नगरसेवक चुनाव के परिणामों में भी मिश्रित जनादेश देखने को मिला।

भाजपा के 4, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के 5, शिंदे गुट की शिवसेना का 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के 5, शिवसेना (उबाठा) के 3 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। इस प्रकार कुल 21 नगरसेवक चुने गए।

निर्दलीय उम्मीदवारों का भी प्रभावी प्रदर्शन इस चुनावी नतीजे से शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस

(शरद पवार गुट) की मजबूत पकड़ स्पष्ट हुई है। साथ ही कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर मतदाताओं का भरोसा जीता।

नगराध्यक्ष पद पर सुजाता एंड्रलवार के चुने जाने के बाद अब नगर परिषद के आगामी प्रशासन और विकास कार्यों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मतगणना की प्रक्रिया सुबह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नगरपालिका परिसर सहित शहर के प्रमुख चौकों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। पुलिस निरीक्षक गणेश कराड के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी।

पराजय के कारणों पर मंथन करेंगे : विधायक केराम पराजय के बाद प्रतिक्रिया देते हुए विधायक भीमराव केराम ने कहा कि शहर में विकास कार्य किए गए, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मतदाताओं के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि हार के कारणों पर आत्ममंथन किया जाएगा।

एमपीएससी सचिव पद पर महेंद्र हरपलकर की नियुक्ति, तीन महीने की देरी पर उठे सवाल



नागपुर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के सचिव पद पर महेंद्र उत्तमराव हरपलकर को नियुक्त किया गया है। यह पद लगभग दो महीने तक खाली रहा, क्योंकि पिछले सचिव के कार्यकाल के बाद नियुक्त किए गए अधिकारी ने पद स्वीकार नहीं किया और सरकार लगभग तीन महीने तक नियुक्ति में देरी करती रही। इस कारण आयोग की परीक्षा परिणाम और अन्य प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं। सचिव पद की रिक्तता के कारण उम्मीदवारों को असमंजस और देरी का सामना करना पड़ा। अंततः सामान्य प्रशासन विभाग ने हरपलकर को सचिव के रूप में नियुक्त किया है।



गोरठेकर परिवार की राजनीतिक ताकत के आगे विरोधी पस्त, उमरी नगर परिषद पर राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट) की लगातार चौथी जीत

नगर परिषद की कुल 20 सदस्यीय सीटों में से 18 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा को मात्र एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा। चुनाव में भाजपा विधायक राजेश पवार ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उनका राजनीतिक दांव उमरी में सफल नहीं हो सका।

चुनाव से पहले मतदाताओं पर विभिन्न माध्यमों से प्रभाव डालने के प्रयास हुए, लेकिन मतदाताओं ने भाजपा उम्मीदवारों को सिरे से नकार दिया। पूरे चुनावी दौर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दी। दिवंगत पूर्व विधायक बापूसाहेब गोरठेकर

उमरी। उमरी नगर परिषद चुनाव में गोरठेकर परिवार की राजनीतिक पकड़ एक बार फिर साबित हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) ने नगर परिषद पर लगातार चौथी बार एकतरफा सत्ता हासिल करते हुए विपक्ष को करारी शिकस्त दी है। नगराध्यक्ष पद के सीधे चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवार शकुंतला भगवान मुदीराज ने भाजपा की स्वप्ना माचेवाड को 1,495 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया।

के बाद उनके पुत्र शिरीषराव गोरठेकर (बाजार समिति सभापति) और जिला बैंक के संचालक एवं विजयी उम्मीदवार कैलास गोरठेकर के नेतृत्व में उमरी में गोरठेकर परिवार का प्रभाव कायम रहा। इस चुनाव में गोरठेकर परिवार की तीसरी पीढ़ी ने भी अपनी राजनीतिक विरासत को बरकरार रखा।

भाजपा के पास विधायक, सहकारी चीनी कारखाने के चेयरमैन और पूर्व नगराध्यक्ष जैसे बड़े चेहरे होने के बावजूद पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं, कांग्रेस ने अपने दम पर एक सीट जीतकर उपस्थिति दर्ज कराई, जो उल्लेखनीय रही। कभी धनुष्य-बाण निशान पर शिवसेना का

भगवा लहराने वाली इस नगर परिषद में इस बार शिवसेना को पूरी तरह सफाया झेलना पड़ा। नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार सहित पार्टी के सभी सात उम्मीदवारों की जमानत तक नहीं बच सकी। चुनावी प्रचार के दौरान विकास कार्यों से अधिक आरोप-प्रत्यारोप और व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी देखने को मिली, जिसका असर मतदान पर साफ नजर आया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में समीकरण कुछ भी हों, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में उमरी की जनता गोरठेकर परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहती है, यह संदेश इस चुनाव परिणाम ने स्पष्ट रूप से दे दिया है।